ISO 9001 & 14001
OHSAS 18001
Power for prosperity

July 2014

# NEEPCO News Flash

A Government of India Miniratna Category-I Corporation

*On-going Hydro-mechanical works at Kameng Hydro Electric Project (KaHEP) in Arunachal Pradesh.*

*Assam Gas Based Power Plant (AGBP) holds one day Hindi Workshop on 13th June, 2014. Thirty employees attended and benifitted from this workshop.*

*Additional Chief Secretary of Meghalaya, Shri Barkos Warjri gave a speech during one day National Conference on Legal Framework on Conservation of Forest and Environment and Implementation of Environmental Safeguards held at NEEPCO on Wednessday, 25th June 2014. The need to formulate a State Environment Policy by the North Eastern States including formulation of State Natural Resource Management and Utilization Policy was stressed upon in the conference.*

*World Environment Day was celebrated at Pare HEP (PHEP) on June 5, 2014. Shri M Debnath, HoP plants trees at NEEPCO residential colony.*

## Power Bites

- Government has set up 'Advisory Group' to be headed by former Power Minister Suresh Prabhu for integrated development of power, coal and renewable energy sectors in a bid to ensure 24 × 7 electricity supply to consumers.
- Government would set up Single-Window Clearance System for Capital-intensive steel, coal and power projects by speeding up approvals for investments. The new facility which could potentially accelerate the execution of new and existing projects and will include contentious environmental and forest clearances that have held up numerous projects across the country. Each project will be set up as Special Purpose Vehicle (SPVs) for which all clearances would have been approved in advance.
- The budget is likely to extend the tax holiday to power projects by one year as the government gears up to provide round-the-clock power to everybody in five years. Only the projects commissioned in this fiscal will be eligible for the sops. Finance Minister Arun Jaitley is expected to provide the incentives to power producers whose projects have been stuck in the absence of fuel linkages and other clearances.
- Power Ministry wants a review of proposal to impose anti-dumping duty on imports of solar gear because country does not have sufficient capacity to make equipments to harness sun's energy to support the kind of thurst it would want to give to solar.
- CSR spending under Companies Act, 2013 : On 27th February, 2014 the Government of India (Ministry) has notified the rules for CSR spending u/s 135 of the new Companies Act, 2013 along with Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 applicable from 1st April, 2014. Under the rule, Government has fixed a threshold limit of 2% of the average 'Net Profits' of the block of previous three years on CSR activities.

All information may be forwarded to managercorpcomm@gmail.com

SQBH4GYA

जुलाई 2014

# नीपको न्यूज फ्लैश

ISO 9001 & 14001
OHSAS 18001

ऊर्जा से समृद्धि

## भारत सरकार का मिनी रत्न श्रेणी-I निगम

*कामेंग जल विद्युत परियोजना (काहेप), अरूणाचल प्रदेश में निर्माणाधीन हाइड्रो - मेकानिकल कार्य।*

*असम गैस आधारित विद्युत संयंत्र (एजीबीपी) में 13 जून, 2014 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला से कुल 30 कर्मचारी लाभान्वित हुए।*

श्री बारकोस वारजरी, अपर मुख्य सचिव, मेघालय ने नीपको में बुधवार, 25 जून, 2014 को वन एवं पर्यावरण संरक्षा के कानूनी पहलुओं तथा पर्यावरण संरक्षण के कार्यान्वयन पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में भाषण दिया। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा राज्य पर्यावरण नीति सहित राज्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और उपयोगिता नीति तैयार करने पर बल दिया गया।

*पारे जल विद्युत परियोजना (पाहेप) में 05 जून, 2014 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। श्री एम. देबनाथ, परियोजना प्रमुख ने नीपको आवासीय कॉलोनी में वृक्षा रोपण किया।*

## पावर बाइट्स

- भारत सरकार के पूर्व विद्युत मंत्री श्री सुरेश प्रभु के नेतृत्व में उपभोक्ताओं के लिए 24×7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्युत, कोयला और अक्षय ऊर्जा के समेकित विकास के लिए सलाहकार समूह का गठन किया है।
- सरकार निवेश अनुमति शीघ्र प्रदान कर विशेष रूप से स्टील, कोयला तथा विद्युत संयंत्रों के लिए पूंजी उपलब्ध कराने हेतु एकल विन्डो प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर रही है। इस नई सुविधा से नई तथा वर्तमान परियोजनाओं की शक्यता के कार्यान्वयन में वृद्धि होगी तथा इससे पर्यावरण तथा वन स्वीकृति के लिए देश भर में लंबित अनेकों विवादास्पद परियोजनाओं का शीघ्र निपटान किया जा सकेगा। प्रत्येक परियोजना को विशेष उद्देश्य निमित (एसपीवीएस) के रूप में स्थापित किया जाएगा जिसके लिए सभी प्रकार की मंजूरी अग्रिम रूप से दी जाएगी।
- सरकार पॉच वर्षों में प्रत्येक को चौबीसो घंटे बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बजट में विद्युत परियोजनाओं के लिए एक वर्ष हेतु कर रियायत को बढ़ाने की संभावना है। इस वित्त वर्ष में चालू होने वाली परियोजनाएं ही इसकी पात्र होंगी। श्री अरूण जेटली, वित्त मंत्री द्वारा उन विद्युत उत्पादकों को प्रोत्साहन देने की उम्मीद है जिनकी परियोजनाएं इंधन लिंकेज और अन्य मंजूरी के अभाव में लंबित है।
- विद्युत मंत्रालय सौर गियर के आयात पर लगाए जाने वाली प्रस्तावित एंटी-डंपिंग शुल्क की समीक्षा करने पर विचार कर रही है क्योंकि सौर उर्जा स्थापित करने पर जितना बल दिया जा रहा है उसके वनस्पत इसके लिए सौर उर्जा के दोहन हेतु पर्याप्त मात्रा में उपस्कर देश में उपलब्ध नहीं है।
- कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सीएसआर पर खर्चः भारत सरकार (मंत्रालय) ने 27 फरवरी 2014 को नई कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के साथ-साथ 01 अपैल, 2014 से लागू कंपनी (कंपनी सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के तहत सीएसआर नियमों को अधिसूचित किया है। इन नियमों के तहत सरकार ने सीएसआर क्रियाकलापों पर विगत तीन खंड वर्षों के औषतन "शुद्ध लाभ" का 2% खर्च करने की सीमा तय कर दी है।

All information may be forwarded to managercorpcomm@gmail.com

SOBHAGYA